

[श्री रघुवीर सिंह शास्त्री]

महीनों और वर्षों लग सकते हैं तो उससे कैसे काम चलेगा ?

दूसरे क्या गवर्नमेंट ने कभी यह सोचा है कि केवल एक फैक्टरी के रहते ऐसी कठिनाइयाँ और समस्याएँ फिर पैदा हो सकती हैं इसलिए कोई दूसरी फैक्टरी भी एकस्प्लोजिव पदार्थ बनाने के लिए जल्दी से जल्दी स्थापित की जाये ? क्या इस बात पर भी गवर्नमेंट ने कभी विचार किया है ?

DR. TRIGUNA SEN : I have replied to almost all the questions, that if the coal mines cannot be exploited many industries like power supply and others will also be affected. It will affect the whole mining industry also ; it is a very serious matter. Because we are interested in the overall mining and industrial development in the country we are very much in it ; we are concerned about it ; we are worried about it. We have also referred this matter to the Labour Ministry to try and see if they can come and help to bring about a settlement about this. Therefore, it is not that we are sitting quiet.

About the other matters mentioned, this factory, I am told is of the ICI, which is a private sector factory. It is very unfortunate that there is only one factory now functioning in the private sector for such an important item on which depends the future development of the whole mining industry.

SHRI S. M. BANERJEE : Take it over ...

DR. TRIGUNA SEN : We have discussed this. We are approaching the Planning Commission for a factory in the public sector. Unfortunately the other private sector factory which is being constructed in Hyderabad has not gone on stream. We are trying to see whether we can have a factory in the public sector. We are trying to see that there is no deficiency in supply of explosives and that the industry does not suffer. We are taking all precautionary measures.

12.32 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Coal Retting (licensing) Amendment Order and papers under Coal Industry Act

बंदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

- (1) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (6) के अन्तर्गत नारियल जटा गलाना (लाइसेंस देना) संशोधन आदेश, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 10 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2141 में प्रकाशित हुआ था। [Placed in Library. See No. LT-3934/70]
- (2) नारियल जटा अधिनियम, 1953 की धारा 19 की उप धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—
 - (ए) वर्ष 1968-69 के लिए नारियल जटा बोर्ड के क्रियाकलापों तथा नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 के लागू किये जाने संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण)। [Placed in Library. See No. LT-3935/70]
 - (ब) 1 अप्रैल, 1969 से 30 सितम्बर, 1969 तक की अवधि के लिए नारियल जटा बोर्ड के क्रियाकलापों तथा नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 के लागू किये जाने सम्बंधी अर्ध-वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा

भंग्रेजी संस्करण)। [Placed
in Library. See No. LT—
3936/70]

समझता हूँ डिस्कशन के लिए ज्यादा टाइम
मिल सकेगा।

श्री राम चरण (खुर्जा) : अध्यक्ष महोदय,
मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। चार दिन हो
गए मैंने एक कार्लिंग प्रॉटेशन नोटिस दी थी
कि एन० डी० एम० सी० में हरिजन मजदूरों
की हड़ताल चल रही है, मुझे मालूम नहीं कि
आपने उसको एडमिट किया या नहीं लेकिन
मेरा आपसे निवेदन है कि आप सम्बन्धित
मन्त्री से यहाँ पर उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य
बिलवा दें।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : अध्यक्ष
महोदय इस हाउस में जो डिस्कशन चल रहा
है उसके लिए आप दो तीन घंटे का टाइम और
बढ़वा दीजिए।

MR. SPEAKER : 5 hours and 10
minutes have already been taken. Those
leaders who were present at the meeting of
the Business Advisory Committee know
that we increased it from 3 hours to 5
hours. Previously, it was four hours, and
then we increased it again by one hour and
it went up to 5 hours. Still, hon. Member
are demanding more time.

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta-
North-East) : This is the third successive
day we are trying to raise discussion of an
important matter by way of Calling Attention
Notice. We are faced with a situation
where the arrests have started running into
five figures over the land movement. In the
other House they had an opportunity of
discussing it. We have to discuss matters
of current importance and it is rather bad
that we are deprived of this opportunity
when we can bring this up within the ambit
of our own rules.

श्री राम चरण (खुर्जा) : अध्यक्ष
महोदय, पहले, एक रिपोर्ट पर 6 घंटे मिलते
थे। इस बार तीन रिपोर्टें हैं और साथ में
पेरुमल कमेटी की रिपोर्ट भी है। उस हिसाब
से इस के लिए 24 घंटे बनते हैं लेकिन आप
इसके लिए कम से कम 20 घंटा जरूर
दीजिए।... (व्यवधान)...

श्री जनेश्वर मिश्र (फूलपुर) : इस पर
बहस होनी चाहिए।... (व्यवधान)...

MR. SPEAKER : How shall we run
the whole programme unless we stick to the
schedule ?

श्री रणधीर सिंह : हम भी एग््री करते
हैं, इस पर बहस जरूर होनी चाहिए।...
(व्यवधान)...

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : चार
रिपोर्टों के लिए कम से कम 8 घंटे जरूर होने
चाहिए। एक रिपोर्ट पर दो घंटे के हिसाब से
कम से कम 8 घंटे जरूर होने चाहिए वरना
थोड़े समय में काफी बोलने वाले रह जायेंगे।
मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इसके लिए 8 घंटे रखे
जायें।

12.35 hrs.

RE. BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : घाट दस घाटमियों की
घावाज एक वक्त में मैं कैसे सुन सकता हूँ ?
स्पीकर को तो ऐसा होना चाहिए जोकि
सभी को एक वक्त में सुन ले। मैंने कार्लिंग
प्रॉटेशन के बारे में सोचा था लेकिन मैं यह
सोचता हूँ कि इसके बारे में कोई डिस्कशन
रख दंगा। आज विज़नेस एडवाइज़री कमेटी
की बैठक में इसको रखा जायेगा और मैं

MR. SPEAKER : I find that hon.
Members are demanding more time. For
the present, I shall increase it by 1 hour.
The Business Advisory Committee...

SHRI RAM CHARAN : 1 hour is not
enough.

MR. SPEAKER : The hon. Member
should listen to me. I am increasing it by
1 hour till the Business Advisory Committee